



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 जून, 1997/2 आषाढ़, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 1997

संख्या रैव०-डी०(जी०) 6-33/86-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20-10-1993 द्वारा 5 नवम्बर, 1993 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि निधान और उपयोग अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) और हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 की धारा 26 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के पश्चात् इन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

यदि इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति इनके सम्बन्ध में कोई आक्षेप करना चाहें या सुझाव देना चाहें, तो वह इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (राजस्व) को उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर भेज सकेंगा ।

इन नियमों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि में प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हों, सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है।

2. नियम 4, 6 और 8 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के खण्ड (III), नियम 6 के खण्ड (7) और नियम 8 के उप-नियम (1) की मद (X) में “भूतपूर्व सैनिकों” शब्दों के लिए “भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, स्वतन्त्रता सैनानियों”, शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 7 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 7 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“पट्टे की मंजूरी.—इन नियमों के अधीन पट्टे, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) और (3) में की सीमाओं के अधीन रहते हुए, स्तम्भ (1) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा मंजूर किए जाएंगे:—

सारणी

मंजूरी प्राधिकारी	भूमि	अनधिक अवधि के लिए
1. कलक्टर	1½ बीघा तक	10 वर्ष
2. मण्डलायुक्त	2½ बीघा तक	20 वर्ष
3. वितायुक्त	5 बीघा तक	50 वर्ष
4. राज्य सरकार	20 बीघा तक	99 वर्ष

परन्तु राज्य सरकार, लोक हित में लोक प्रयोजन के लिए 20 बीघा से अधिक क्षेत्र का पट्टा प्रदान कर सकेगी।”

4. नियम 10 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 10 में शब्दों “प्रारूप-अ” के पश्चात् (नवीनतम जमाबन्दी, तृतीया, विक्रय मूल्य को पांच साला औसत और प्रस्तावित भूमि की नवीनतम बाजारी कीमत) शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. नियम 13 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 13 में—

(i) उप-नियम (2) में दूसरी बार आए “उप-मण्डलाधिकारी (त्रिविल) के माध्यम से” शब्दों के पश्चात् “और जहां भूमि 2½ बीघा से अधिक हो, मण्डलायुक्त के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) उप-नियम (2) के अधीन कलक्टर की रिपोर्ट पर विचार किए जाने से पूर्व, मंजूरी प्राधिकारी, भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने के न्यायोचित्य और उपयुक्तता के सम्बन्ध में सरकार के उस विभाग, जिससे आवेदक, संस्था या निगमित निकाय के रूप में, रजिस्ट्रीकृत है या मान्यता प्राप्त है या अपने क्रिया-कलाप के लिए सम्बद्ध है, के विचार अभिनिश्चित करेगा।”

6. नियम 20 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 20 में, “पट्टा रद्द कर सकेगा और शब्दों के लिए” उसके द्वारा-मंजूर पट्टों को रद्द कर सकेगा और अन्य मामलों में शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. नियम 26 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 26 में, शब्दों और चिन्हों “कलक्टर”, के पश्चात्, “मण्डलायुक्त”, शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

8. नियम 27 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 27 में आए शब्द “कलक्टर” के पश्चात् चिन्ह, और शब्द “मण्डलायुक्त” रखा जाएगा।

आदेश द्वारा,

आर० भट्टाचार्य,
विज्ञापित एवं सचिव।

[Authoritative English Text of Government Notification No. Rev. D(G) 6-33/86-III, dated the 11th June, 1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

—REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 1997

No. Rev. D (G) 6-33/86-III.—In exercise of the powers vested in him under section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 published in the Rajpatra (Extraordinary) Himachal Pradesh dated the 5th November, 1993 vide this Department Notification of even number, dated 20-10-1993, and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public as required under sub-section (3) of section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act 1974 and under sub-section (2) of section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 and a notice is hereby given that the said rules shall be finalised after 30 days of publication of this notification.

If any person likely to be affected by the said rules has any objections or suggestions to make in respect of these rules, he may send the same to the Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within the above stipulated period.

Objections or suggestions, if any, in respect of these rules, received within the period specified above, shall be considered by the Government before finalising these draft rules, namely :—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Second Amendment) Rules, 1997.

2. *Amendment of rules 4, 6 and 8.*—In clause (iii) of rule 4, clause (7) of rule 6 and item (x) of sub-rule (1) of rule 8 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 (hereinafter called the said rules) for the words “ex-servicemen” the words “ex-servicemen, war-widows, freedom fighters” shall be substituted.

3. *Substitution of rule 7.*—For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“7. *Sanction of lease.*—The leases under these rules shall be sanctioned by the authorities mentioned in Column (1) subject to limits given in columns (2) and (3) in the Table below:—

TABLE

Sanctioning authority 1	upto the area 2	for the period not exceeding 3
1. Collector	upto 1½ bighas	10 years
2. Divisional Commissioner	upto 2½ bighas	20 years
3. Financial Commissioner	upto 5 bighas	50 years
4. State Government	upto 20 bighas	99 years

Provided that the State Government may grant the lease of an area exceeding 20 bighas for public purposes in the public interest.

4. *Amendment of rule 10.*—In rule 10 of the said rules, after the words “Form –A” the words and brackets “(alongwith copy of latest jamabandi, tatima, five years average sale price and latest market value of the proposed land)”, shall be inserted.

5. *Amendment of rule 13.*— In rule 13 of the said rules :—

(i) in sub-rule (2), after the words “through Sub-Divisional Officer (Civil)” occurring for the second time, the words “and where the area exceeds 2½ bighas through the Divisional Commissioner” shall be inserted.

(ii) after sub-rule (2), the the following new sub-rule (3) shall be added, namely :—

“(3) Before considering the report of the Collector, received under sub-rule (2), the sanctioning authority shall, in relation to the justification and appropriateness for the grant of lease of land, ascertain the views of the department of Government with which the applicant, being an Institution or a Corporate body, is either registered or recognised, or is co-related in its activities.

6. *Amendment of rule 20.*—In rule 20 of the said rules, for the words and sign “cancel the lease, and,” the words “cancel the lease sanctioned by him and in other cases” shall be substituted.

7. *Amendment of rule 26.*—In rule 26 of the said rules, after the word and sign “Collector”, the words and sign, “Divisional Commissioner”, shall be inserted.

8. *Amendment of rule 27.*—In rule 27 of the said rules, after the word and sign, “Collector”, occurring for the first time, the words, “Divisional Commissioner” shall be inserted and after the words “Collector” occurring for the second time, the sign, and words “Divisional Commissioner” shall be inserted.

By order,

R. BHATTACHARYA,
Financial Commissioner-cum-Secretary.